# PM-UShA Review in Rajasthan (Project Progress, Funding Pattern, Quality Results).

The Chief Secretary of Rajasthan V. Srinivas surveyed progress of the projects that were being implemented under the centrally sponsored **Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-UShA)** in a meeting at the Manthan Hall, Secretariat, Jaipur on 20 February. The review was aimed at optimal use of resources developed within PM-uShA and the provision of quantifiable enhancement of the quality of higher education. The Chief Secretary also instructed the department to determine the effects of the success stories and achievements of the scheme, to ensure there are results of the scheme in the strengthening of institutions, quality of teaching learning and support of research in the state in the universities and colleges.

## Key Highlights

- Projects approved in total (RUSA 1.0 and 2.0): 130 (approved in 5 universities and 116 colleges respectively)
- Total sanctioned cost: ₹611 crore
- Expenditure so far: ₹534.84 crore
- Works completed: 106
- Under progress: 24 (to be completed by 30 September 2026)
- Pattern of funding: 60% Centre share + 40% State share

## Project Financial Performance and Project Status.

- With RUSA 1.0 and 2.0, Rajasthan was granted approvals on 130 projects in 5 universities and 116 colleges at a cumulative cost of 611 crore.
- Opposite this, there has been expenditure of = -534.84 crore and completion of 106 works.
- The rest of the works are also in progress and are expected to be finalized by 30 September 2026.

## Proposal of PM-Usha Approvals and Supplementary Allocation.

- Under PM-uShA, the Central Government was given approval of 34 projects by cost of 330 crore to 4 state funded universities and 30 government colleges.
- All these are still in progress and up to now a total of 90 crores have already been expended.
- Utilisation certificates have been submitted to Government of India and proposal of further allotment of 37 crore additional in FY 202526 has been and is being forwarded.

## Focus Areas Under the Scheme

- New building construction
- Refurbishment and renovation.
- Buying of new and modern machinery.
- Futuristic research and innovation.
- General consolidation of institutions of higher education using quality-based interventions.

## Conclusion

The review of PM-uSha projects of Rajasthan points out a high completion rate of 106 works out of 130 under RUSA 1.0 and 2.0 and the rest of the works are scheduled till 30 September 2026. The utilisation focus, quantifiable quality enhancement, and measureable impact assessment are in tandem with the outcome-based governance and institutional strengthening in higher education by infrastructural, equipment, and research-oriented support.

---

## MCQS (Ras Prelims )

MCQ 1: In relation to the PM-UShA-related project implementation in Rajasthan, take into account the following statements:

1. With RUSA 1.0 and 2.0, 130 projects were granted that had a total cost of ₹611 crore.

RASonly

2. Among these, 106 works have been done at an expenditure of 534.84 crore.

3. The rest of the works will be to be completed by 30 September 2026.

Which of the above-presented statements is/are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: Rajasthan has 130 approved projects under RUSA 1.0 and 2.0 which will have a total approved cost of 611 crore. Status of progress shows that the company has expended ₹534.84 crore and has completed 106 works. The other 24 pieces are still in the process where they are expected to be completed by 30 September 2026.

MCQ 2: The scheme covered in the news is funded according to the following pattern:

(a) 50% Centre and 50% State

(b) 60% Centre and 40% State

(c) 70% Centre and 30% State

(d) 75% Centre and 25% State

Answer: (b)

Explanation: The scheme has been financed in a 60: 40 sharing basis with 60 percent being offered as the share of the Centre and 40 percent offered as the share of the State. The importance of this pattern of funding as a prelim question on centrally sponsored schemes and the design of scheme as a cost sharing scheme.

MCQ 3: Given the following assertions regarding the PM-uShA project approvals in Rajasthan:

1. The Central Government sanctioned 34 projects at 330 crore of 4 state-funded universities as well as 30 government colleges.

2. 90 crore is the amount that has been expended on these projects.

3. The request of an extra 37 crore allocation has been submitted after submission of utilisation certificates to FY 2025-26.

RASonly

Which of the statements provided above are/is/are correct?

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: There are 34 approved projects (4 state-funded universities and 30 government colleges) in the project set under PM-uSha with a cost amounting to 330 crore. Expenditure of 90 crore till now has been reported and utilisation certificates have been mailed along with a proposal of an extra 37 crore to be allocated in FY 2025-26.

---

# राजस्थान में पीएम-उषा की समीक्षा (परियोजना प्रगति, वित्तीय पैटर्न, गुणवत्ता परिणाम)

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 20 फरवरी को सचिवालय, जयपुर के मंथन सभागार में आयोजित बैठक में केन्द्रीय प्रवर्तित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा का उद्देश्य पीएम-उषा के अंतर्गत सृजित संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में मापनीय और ठोस सुधार लाना था। मुख्य सचिव ने विभाग को योजना की सफलताओं और उपलब्धियों का प्रभाव आकलन कराने के निर्देश भी दिए, ताकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता, तथा अनुसंधान समर्थन में वास्तविक परिणाम दिखाई दें।

## प्रमुख बिंदु

- कुल स्वीकृत परियोजनाएँ (रूसा 1.0 और 2.0): **130** (क्रमशः **5 विश्वविद्यालयों** और **116 महाविद्यालयों** में)
- कुल स्वीकृत लागत: **₹611 करोड़**
- अब तक व्यय: **₹534.84 करोड़**
- पूर्ण कार्य: **106**
- प्रगतिरत कार्य: **24** (पूर्णता लक्ष्य: **30 सितंबर 2026**)
- वित्तपोषण पैटर्न: **60% केन्द्रांश + 40% राज्यांश**

RASonly

## परियोजना स्थिति और वित्तीय प्रगति

- रूसा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत राजस्थान में **5 विश्वविद्यालयों** और **116 महाविद्यालयों** में कुल **130 परियोजनाएँ** स्वीकृत हुईं, जिनकी कुल लागत **₹611 करोड़** है।
- इसके विरुद्ध अब तक **₹534.84 करोड़** व्यय किए जा चुके हैं और **106 कार्य** पूर्ण हो चुके हैं।
- शेष **24 कार्य** प्रगति पर हैं और इन्हें **30 सितंबर 2026** तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

## पीएम-उषा अनुमोदन और अतिरिक्त आवंटन प्रस्ताव

- पीएम-उषा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा **4 राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों** और **30 राजकीय महाविद्यालयों** के लिए **34 परियोजनाएँ ₹330 करोड़** की लागत से स्वीकृत की गईं।
- इन सभी परियोजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं और अब तक **₹90 करोड़** व्यय किए जा चुके हैं।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिए गए हैं और **वित्तीय वर्ष 2025-26** में **₹37 करोड़** के अतिरिक्त आवंटन हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

## योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य-क्षेत्र

- नवीन भवन निर्माण
- जीर्णोद्धार और नवीनीकरण
- नए और आधुनिक उपकरणों/मशीनरी की खरीद
- अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा
- गुणवत्ता-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों का समग्र सुदृढ़ीकरण

## निष्कर्ष

राजस्थान में पीएम-उषा (रूसा 1.0 और 2.0) के अंतर्गत **130 में से 106 कार्यों** का पूर्ण होना उच्च पूर्णता दर को दर्शाता है, जबकि शेष कार्यों को **30 सितंबर 2026** तक पूरा करने की योजना है। संसाधनों के उपयोग पर जोर, गुणवत्ता में मापनीय सुधार, और प्रभाव आकलन की दिशा में कदम उच्च शिक्षा में परिणाम-आधारित शासन तथा अवसंरचना, उपकरण और अनुसंधान-आधारित समर्थन के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण को आगे बढ़ाते हैं।

---

## बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

**MCQ 1:** राजस्थान में पीएम-उषा से संबंधित परियोजना कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- रूसा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत 130 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं जिनकी कुल लागत ₹611 करोड़ है।
- इनमें से ₹534.84 करोड़ व्यय कर 106 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
- शेष कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने हैं।

RASonly

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**
**व्याख्या:** राजस्थान में रूसा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत 130 परियोजनाएँ कुल ₹611 करोड़ की लागत से स्वीकृत हैं। प्रगति स्थिति के अनुसार ₹534.84 करोड़ व्यय कर 106 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष 24 कार्य प्रगतिरत हैं और इन्हें 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय है।

---

**MCQ 2:** समाचार में वर्णित योजना का वित्तपोषण किस पैटर्न के अनुसार है?
(a) 50% केन्द्रांश और 50% राज्यांश
(b) 60% केन्द्रांश और 40% राज्यांश
(c) 70% केन्द्रांश और 30% राज्यांश
(d) 75% केन्द्रांश और 25% राज्यांश

**उत्तर: (b)**
**व्याख्या:** योजना में 60:40 का वित्तपोषण ढांचा अपनाया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रांश और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यांश के रूप में निर्धारित है। यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लागत-साझेदारी मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे योजना के वित्तीय दायित्व केन्द्र और राज्य के बीच विभाजित होते हैं।

---

**MCQ 3:** राजस्थान में पीएम-उषा परियोजना स्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- केन्द्र सरकार ने 4 राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों तथा 30 राजकीय महाविद्यालयों के लिए ₹330 करोड़ की लागत से 34 परियोजनाएँ स्वीकृत कीं।
- इन परियोजनाओं पर अब तक ₹90 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹37 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 केवल
(b) 1 और 2 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**
**व्याख्या:** पीएम-उषा के अंतर्गत 4 राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और 30 राजकीय महाविद्यालयों के लिए 34 परियोजनाएँ ₹330 करोड़ की लागत से स्वीकृत हैं। इन पर अब तक ₹90

RASonly

करोड़ का व्यय रिपोर्ट किया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे जाने के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹37 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन हेतु प्रस्ताव भी अग्रेषित किया गया है।

## Indian Air Force Aerobic Show at Jal Mahal Jaipur.

A aerobic performance, a demonstration by an Indian Air Force of precision flying and synchronized aerial action by the Surya Kiran Aerobatic Team and the Sarang Helicopter Display Team, was held at Jal Mahal, Jaipur on 20 February. Thousands of spectators attended the event which was attended by Cabinet Minister Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, and the administrative personnel, representatives of the citizen, senior defence officials, NCC cadets, school students and citizens. The show emphasised high training, discipline and teamwork using complicated formations, spacing control, and coordinated movements. The organisers assured that the central and the larger aerobatic performance will be held in the same venue on 22 February and the final preparations will be made.

### Key Highlights

- Location: Jal Mahal, Jaipur (restricted to the Jal Mahal embankment area)

- Date of display: 20 February
- Team members: Surya Kiran Aerobatic Team and Sarang Helicopter Display Team.
- Dignitary present: Cabinet Minister Cabinet Minister Colonel Rajyavardhan Singh Rathore.
- Main show date: 22 February

## What the Teams Displayed

### Sarang Helicopter Display Team.

- The action was done with five colourful helicopters.
- Displayed close-formation flight, intricate air formations, accuracy of spacing, weight support and coordination.

### Surya Kiran Aerobatic Team

- Flew Hk-132 (red-white stripe) jet airplane.
- Performed manoeuvre including loops, barrel rolls, inverted flying, formation flying, and the most popular manoeuvre, the DNA formation.

Tricolour smoke trails made the visual impact of patriotism really strong.

### Local Connect and Youth Inspiration

**There are three pilots related with the Surya Kiran performance whose residence is in Jaipur:**

- Wing Commander Rajesh Kajla
- Ankit Vashishth is a wing commander.
- Sanjesh Singh is a Squadron Leader.

The event served as an inspirational event to the youth and the NCC cadets, where they were motivated to be disciplined, brave and willing to offer their services to the military.

## Objectives and Benefits

### Objectives

- Educate the people about the air power and the professional flying standards.
- Motivate students and NCC cadets by live exhibitions of competence and cooperation.
- Enhance civil-military relationships by way of outreach activities.

### Benefits

- Encourages national pride and civic participation by and through organised mass exhibitions.

RASonly

- Promotes the youth to be involved in career opportunities and activities of the NCC that relate to defence.
- Exhibits institutional capability in terms of precision, safety and coordination.

## Conclusion

The Jal Mahal aerobic show in Jaipur was a demonstration of the discipline, coordination, and high flying skills of the Indian Air Force by demonstrating helicopter precision formations and jet aerobatics. The event further supported the spirit of patriotism since there was a strong involvement of the people and a well-defined outreach aspect, which had a youth focus. The primary aerobatic performance to be delivered on 22 February is likely to broaden the performance and is likely to continue being one of the primary points of interaction with the population in the city.

---

## MCQs (Prelims Pattern)

MCQ 1**:** On 20 February, the aerobatic display in Jal Mahal, Jaipur featured one or more of the following Indian Air Force teams?

(a) Surya Kiran Aerobatic Team and Sarang Helicopter Display Team.

(b) Tejas Demo Team and Sarang Helicopter Display Team.

Both of these groups have been selected for 2015 because they are recent and have never competed before in the UK.

(d) Akash Ganga Team and Sarang Helicopter Display Team.

Answer: (a)

Explanation : The occasion at Jal Mahal, 20 February presented aerial acts by 2 individual groups, namely, Surya Kiran Aerobatic Team and Sarang Helicopter Display Team. The presentation was structured as a communal gathering, where many people were present, and it was a prelude to the actual aerobic performance planned on 22 February.

MCQ 2: In the case of the Jal Mahal aerobic display, the following statements can be considered:

1. Sarang Helicopter Display Team had a performance on five helicopters.

2. The Hawk Mk-132 jet flyers belonged to Surya Kiran Aerobatic Team.

3. The central aerobatic performance on Jal Mahal is to take place on 22 February.

What is/are the correct statement/s above?

(a) 1 only

RASonly

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: Sarang did the helicopter section with five helicopters and Surya Kiran did the jet aerobatics with Hawk Mk-132 aircrafts. It is also mentioned clearly in the event note that the full and more detailed aerobatic performance will be held at Jal Mahal on 22 February and preparations are already complete on the same.

MCQ 3: According to the news, which of the following officials were present at the Jal Mahal aerobatic display in Jaipur?

(a) Cabinet Minister Colonel Rajyavardhan Singh Rathore.

(b) Chief Secretary V. Srinivas

(c) Governor of Rajasthan

(d) Chief of Air Staff

Answer: (a)

Explanation: Under the programme, the occurrence of Cabinet Minister Colonel Rajyavardhan Singh Rathore during the event is explicitly recorded. Administrative officials, the representatives of the population, senior defence officers, NCC cadets, school students, and a very big number of citizens were also present to see the Surya Kiran and Sarang performances.

---

## जल महल, जयपुर में भारतीय वायु सेना का एरोबैटिक शो

20 फरवरी को जल महल, जयपुर में भारतीय वायु सेना द्वारा सटीक उड़ान और समन्वित हवाई करतबों का प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने जटिल फॉर्मेशन, नियंत्रित दूरी और तालमेलपूर्ण मूवमेंट्स के माध्यम से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, अनुशासन और टीमवर्क का परिचय दिया। कार्यक्रम में हजारों दर्शक उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ रक्षा अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इसी स्थल पर 22 फरवरी को मुख्य और अधिक विस्तृत एरोबैटिक शो आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अंतिम तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं।

RASonly

## प्रमुख बिंदु

- स्थान: जल महल, जयपुर (जल महल की पाल/परिसर क्षेत्र में दर्शकों की उपस्थिति)
- प्रदर्शन की तिथि: 20 फरवरी
- भाग लेने वाली टीमें: सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम
- प्रमुख अतिथि: कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
- मुख्य शो की तिथि: 22 फरवरी

## टीमों ने क्या प्रदर्शित किया

### सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम

- **पाँच** रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ प्रदर्शन
- क्लोज-फॉर्मेशन उड़ान, जटिल हवाई संरचनाएँ, दूरी की सटीकता, संतुलन और तालमेल का प्रदर्शन

### सूर्य किरण एरोबैटिक टीम

- **हॉक एमके-132** (लाल-सफेद रंग-रूप) जेट विमानों से उड़ान
- लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग और लोकप्रिय **'डीएनए'** संरचना जैसे करतब
- तिरंगे रंगों की धुएँ की लकीरों से देशभक्ति का प्रभावशाली दृश्य

### स्थानीय जुड़ाव और युवाओं को प्रेरणा

- सूर्य किरण टीम के प्रदर्शन से जुड़े तीन पायलट **जयपुर निवासी** हैं:
  - विंग कमांडर राजेश काजला
  - विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ
  - स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह
- कार्यक्रम युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरक रहा, जिसमें अनुशासन, साहस और सैन्य सेवा के प्रति उत्साह को बल मिला।

## उद्देश्य और लाभ

### उद्देश्य

- वायु शक्ति और पेशेवर उड़ान मानकों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना
- विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स को कौशल और टीमवर्क के प्रत्यक्ष प्रदर्शन से प्रेरित करना
- जन-संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक–सैन्य संबंधों को मजबूत करना

### लाभ

- संगठित सार्वजनिक प्रदर्शनों के जरिए राष्ट्रीय गौरव और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा

RASonly

- युवाओं में एनसीसी और रक्षा से जुड़े करियर अवसरों के प्रति रुचि और प्रेरणा
- सटीकता, सुरक्षा और समन्वय के आधार पर संस्थागत क्षमता का प्रदर्शन

## निष्कर्ष

जल महल पर आयोजित एरोबैटिक शो ने हेलिकॉप्टर फॉर्मेशन और जेट एरोबैटिक्स के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उच्च स्तरीय उड़ान क्षमता, अनुशासन और समन्वय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। व्यापक जनभागीदारी और युवा-केंद्रित संदेश के कारण यह आयोजन देशभक्ति और प्रेरणा का सशक्त मंच बना। 22 फरवरी को प्रस्तावित मुख्य एरोबैटिक शो में और अधिक विस्तृत तथा भव्य हवाई करतब देखने को मिलेंगे, जिससे यह शहर में जन-संपर्क और प्रेरणा का प्रमुख कार्यक्रम बना रहेगा।

---

## बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

**MCQ 1:** 20 फरवरी को जल महल, जयपुर में आयोजित एरोबैटिक प्रदर्शन में भारतीय वायु सेना की कौन-सी टीमें शामिल थीं?
(a) सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम
(b) तेजस डेमो टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम
(c) आकाश गंगा टीम और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम
(d) आकाश गंगा टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम

**उत्तर: (a)**
**व्याख्या:** 20 फरवरी को जल महल में आयोजित कार्यक्रम में दो प्रमुख टीमें शामिल थीं—सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम। यह सार्वजनिक प्रदर्शन बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति में हुआ और इसे 22 फरवरी को होने वाले मुख्य एवं विस्तृत एरोबैटिक शो के पूर्वाभ्यास/पूर्व-आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया।

---

**MCQ 2:** जल महल एरोबैटिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने पाँच हेलिकॉप्टरों के साथ प्रदर्शन किया।
- सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हॉक एमके-132 जेट विमानों से एरोबैटिक्स किया।
- जल महल पर मुख्य एरोबैटिक शो 22 फरवरी को आयोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 केवल
(b) 1 और 2 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**
**व्याख्या:** सारंग टीम ने हेलिकॉप्टर खंड में पाँच हेलिकॉप्टरों के साथ क्लोज-फॉर्मेशन और समन्वय का प्रदर्शन किया, जबकि सूर्य किरण टीम ने हॉक एमके-132 जेट विमानों से जटिल एरोबैटिक

RASonly

करतब किए। कार्यक्रम विवरण के अनुसार 22 फरवरी को इसी स्थल पर मुख्य और अधिक विस्तृत एरोबैटिक शो आयोजित होना है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

---

**MCQ 3:** समाचार के अनुसार, जल महल एरोबैटिक प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारी/व्यक्ति उपस्थित था?
(a) कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
(b) मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास
(c) राजस्थान के राज्यपाल
(d) वायु सेना प्रमुख

**उत्तर: (a)**
**व्याख्या:** कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति दर्ज की गई। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ रक्षा अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद थे, जिन्होंने सूर्य किरण और सारंग के हवाई करतबों को देखा।

RASonly

# National Cyber Security Conference, Inclusive Access to Justice and Special cyber Courts in Rajasthan.

- A national conference on three days on the topic of cyberspace security: awareness, protection and equal access to justice was launched on 20 February at the Rajasthan International Centre (RIC), Jaipur.
- Justice Surya Kant emphasized that digital revolution has enhanced the access to governance, services and communication but abuse poses serious challenges.
- He emphasized that cyber security does not only apply in securing bank accounts, but also in securing institutional trust.
- Chief Minister Bhajanlal Sharma referred to cyber security as a collective determination and that awareness of the people is the best defense against cybercrime.
- Others: Chief Minister declared institute of Special Cyber Courts in Rajasthan to enhance control and prevention of cyber crimes.

## The main messages by Justice Surya Kant.

- Digital arrest is not, and can never be, a court procedure, and it has no presence as a legal process it is a wholesome fraud.
- The longer-term cyber security would be to make citizen education an obligatory component of the learning process, and to have all the institutions as coordinated partners.

- The rule, which is important on its own, is that we should always think before we speak, or do something, so that it is the more crucial in the digital realm where a single click of the mouse button can result in permanent harm.
- Cyber security is like an example of ancient practical wisdom in contemporary manifestation, doing something mindful and wary.
- He welcomed the shift of the state to cyber courts and recognized the innovations by the Rajasthan High Court and the State Legal Services Authority and stated that the state justice can be real only when it can be accessed.

### Primary Statements and pledges by the Chief Minister Bhajanlal Sharma.

- Cybercrime is increasing along with the spread of technology and the best preventative measure is awareness.

## The state is acting hard in controlling the cybercrime:

### Operation Anti Virus: attack against the cyber criminals, punishing them to jail.

- Formation of the Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C) in control and prevention of cybercrime.
- Special Cyber Courts will also be established in Rajasthan to exercise firmer control over the cyber offences.
- It was connected to the governance reforms and he identified that the citizens are becoming digitally connected as the Digital India vision states that citizens are becoming digitally connected to:

### Bank services, crop cover, pensions, and even courts.

- He has noted that the use of e-courts portal, video-conferencing hearings and online complaint systems has led to increased transparency and ease of access to justice, including to isolated communities.
- The state of Rajasthan is implementing effectively methods of delivering justice which are presented by the central government, which are three, and which seek to deliver justice more quickly, and developing e-courts at a high pace.
- The purpose of the state has been mentioned explicitly: no space to criminals in Rajasthan.

RASonly

## Institutional Placements and Essential movements in the Event.

### In the case of Rajasthan State Legal Services Authority, it is stated:

- Mediation online system and Lok Adalat system (e-Samadhan) launched.
- Publication of a handbook on mediation.
- Introduction of Mahila Panchayat Pan Rajasthan.

### Other releases/initiatives were:

Legal Services Ready Reckoner 2026 is a personal accounting package designed to process all accounting requirements that a person or a corporation needs to maintain its finances.

- Campaign of awareness of the law at school.
- Cyber awareness handbook

In the program which was named Sports for Awareness: Udaan 2.0, prizes were given to winning differently-abled children in sports events.

### Dignitaries Present

- High Court of Rajasthan: Justice Sanjeev Prakash Sharma is the acting Chief Justice of the court.
- Supreme Court Judges: Justice Ahsanuddin Amanullah and Justices Rajesh Bindal and justices Prasanna bhalchandra Varale and Justice N. Kotiswar Singh.
- High court of Rajasthan: Judge: Justice Dr. Pushpendra Singh Bhati.
- Deputy Chief Ministers On leave: Diya Kumari and Dr. Premchand Bairwa.
- Ministers in Law and legal affairs, Rajasthan: Jogaram Patel.
- Other government representatives, officials, jurists and jurists.

### Why this is important to RAS Prelims/Mains

- Not only financial safety but also directly impacting the public trust in institutions, cyber security has now become a factor in it.
- The easy directive on the common fraudulent activity of so-called digital arrests is a powerful aid to raising awareness and concentration of law enforcement.
- The introduction of Special Cyber Courts is an indication of transition towards delivery of specialised forms of justice on cyber criminal offences.
- Governance reforms to enhance access to justice are reflected by expansion of e-courts, internet complaints and video hearings.

RASonly

## Conclusion

The Jaipur conference framed cyber security as protection of institutional trust, not just bank accounts. It warned that “digital arrest” is pure fraud, strengthening public vigilance. Rajasthan’s Special Cyber Courts, Operation Anti Virus and proposed R4C signal specialised action. E-courts, video hearings and e-Samadhan expand inclusive access to justice.

---

## MCQs (Prelims Pattern)

MCQ 1: In the context of the national conference on cyber security, which was conducted in Jaipur, the following statements can be taken into consideration:

1. The conference was conducted in Rajasthan International Centre (RIC), Jaipur.

2. It was to be a three day national conference on cyber security and access to justice.

3. Specific focus was given on the awareness as one of the measures to prevent cybercrime.

Which of the statements provided above are/is correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation : It was held at RIC, Jaipur and was a three-day national conference. The theme linked cyber security to awareness, protection, and having equal access to justice, and the importance of awareness as a good protection against cybercrimes was highly emphasized.

MCQ 2: What was said at the conference on the concept of digital arrest?

(a) It is a judicial procedure which is recognised in cases of cybercrime.

(b) It is a legitimate instrument of expediting arrests in the digital frauds.

(c) It is not a judicial process, and is a kind of fraud.

(d) It is a procedure of the police that is running on e-courts portal.

Answer: (c)

RASonly

Rationale: Justice Surya Kant said that there is no such thing as digital arrest as a judicial process and should be regarded as a fraud. This was done to create awareness to the people and discourage them to give in to such scam practices.

MCQ 3: Take into account the following statements regarding measures and initiatives which were emphasized during the event:

1. It was reported that the Chief Minister declared that Special Cyber Courts would be created in Rajasthan.

2. The state was action against the cyber criminals in operation anti virus.

3. An e-Samadhan online mediation and Lok Adalat system was opened.

Which one or neither of the above-mentioned statements is/are right?

(a) 1 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (d)

Explanation: It involved a big declaration on Special Cyber Courts, explained enforcement business in Operation Anti Virus, and logged on to openings by the State Legal Services Authority such as the e-Samadhan site to mediate online and Lok Adalat-related access.

---

## राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन, न्याय तक समावेशी पहुंच और राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट

- “साइबर सुरक्षा—जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच” विषय पर **तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन** का उद्घाटन **20 फरवरी** को **राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), जयपुर** में हुआ।
- **जस्टिस सूर्यकांत** ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने शासन, सेवाओं और संवाद तक पहुंच को बढ़ाया है, लेकिन दुरुपयोग से गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं।
- उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा केवल **बैंक खातों की सुरक्षा** तक सीमित नहीं है, बल्कि यह **संस्थागत विश्वास की रक्षा** का विषय भी है।
- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा** ने साइबर सुरक्षा को **सामूहिक संकल्प** बताते हुए कहा कि नागरिकों की **जागरूकता** ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी कवच है।

RASonly

- मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम को मजबूत करने के लिए **राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट** स्थापित किए जाने की घोषणा की।

## जस्टिस सूर्यकांत के प्रमुख संदेश

- **"डिजिटल अरेस्ट"** कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है और न ही इसका कोई वैधानिक अस्तित्व है; यह **पूर्णतः धोखाधड़ी** है।
- दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा के लिए **नागरिक शिक्षा** को सीखने की प्रक्रिया का **अनिवार्य घटक** बनाना होगा और सभी संस्थाओं को **समन्वित साझेदारों** की तरह मिलकर काम करना होगा।
- "**सोचकर बोलो, समझकर कार्य करो**" का अनुशासन डिजिटल दुनिया में और अधिक आवश्यक है, क्योंकि एक क्लिक से तुरंत और गंभीर नुकसान हो सकता है।
- साइबर सुरक्षा मूल रूप से सावधानी और जागरूकता पर आधारित **प्राचीन व्यावहारिक बुद्धिमत्ता** का आधुनिक रूप है।
- उन्होंने राजस्थान के साइबर कोर्ट की दिशा में पहल का स्वागत किया, **राजस्थान उच्च न्यायालय** और **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण** के नवाचारों की सराहना की, और कहा कि न्याय तभी वास्तविक है जब वह **सुलभ** हो।

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख वक्तव्य और घोषणाएं

- तकनीक के विस्तार के साथ **साइबर अपराध बढ़ रहे हैं**, और इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय **जागरूकता** है।
- राज्य सरकार साइबर अपराध नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठा रही है:
    - **ऑपरेशन एंटी वायरस** के तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया।
    - साइबर अपराधों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए **राजस्थान साइबर क्राइम कण्ट्रोल सेंटर (आर4सी)** की स्थापना की जा रही है।
- साइबर अपराध पर सख्त नियंत्रण हेतु **विशेष साइबर कोर्ट** स्थापित किए जाएंगे।
- डिजिटल इंडिया दृष्टि के तहत नागरिक डिजिटल माध्यम से:
    - बैंकिंग सेवाओं, फसल बीमा, पेंशन और न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़ रहे हैं।
- **ई-कोर्ट पोर्टल**, **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई**, और **ऑनलाइन शिकायत प्रणाली** से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है और दूरदराज क्षेत्रों तक न्याय अधिक त्वरित व सुलभ हुआ है।
- केन्द्र सरकार द्वारा लागू **तीन नए कानूनों** को राजस्थान में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे न्याय शीघ्र पहुंचाने की दिशा में गति बढ़ी है, और **ई-कोर्ट्स** का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
- राज्य का उद्देश्य स्पष्ट किया गया: **राजस्थान में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।**

RASonly

## कार्यक्रम में संस्थागत पहल और प्रमुख गतिविधियां

### राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

- **ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत मंच "ई-समाधान"** का शुभारंभ
- **मध्यस्थता पर हैंडबुक** का विमोचन
- **"महिला पंचायत पैन राजस्थान"** का शुभारंभ

### अन्य पहल/विमोचन

- **लीगल सर्विसेज रेडी रेकनर 2026**
- **स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान**
- **साइबर जागरूकता हैंडबुक**

### पुरस्कार वितरण

- **"स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस: उड़ान 2.0"** के तहत खेल प्रतियोगिताओं में विजेता **दिव्यांग बच्चों** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

### उपस्थित प्रमुख गणमान्य

- राजस्थान उच्च न्यायालय: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश **जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा**
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: **जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह**, **जस्टिस राजेश बिंदल**, **जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र वराले**, **जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह**
- राजस्थान उच्च न्यायालय: **जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी**
- उपमुख्यमंत्री: **दिया कुमारी** एवं **डॉ. प्रेमचंद बैरवा**
- राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य मंत्री: **जोगाराम पटेल**
- अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, न्यायाधिपतिगण एवं विधि विशेषज्ञ

### आरएएस प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के लिए महत्व

- साइबर सुरक्षा अब केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं, बल्कि **संस्थागत विश्वास और जन-भरोसे** से सीधे जुड़ा विषय है।
- "डिजिटल अरेस्ट" जैसे सामान्य साइबर ठग-तरीकों पर स्पष्ट चेतावनी नागरिक **जागरूकता** और **कानून-व्यवस्था** दोनों के लिए उपयोगी है।
- **विशेष साइबर कोर्ट** की घोषणा साइबर अपराधों के लिए **विशेषीकृत न्याय-प्रणाली** की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- **ई-कोर्ट्स, ऑनलाइन शिकायत, वीडियो सुनवाई** जैसे सुधार **न्याय तक पहुंच** को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाते हैं।

RASonly

## निष्कर्ष

जयपुर सम्मेलन ने साइबर सुरक्षा को केवल बैंक खातों की नहीं, संस्थागत विश्वास की रक्षा बताया। "डिजिटल अरेस्ट" को पूर्ण धोखाधड़ी बताकर जन-सतर्कता बढ़ी। विशेष साइबर कोर्ट, ऑपरेशन एंटी वायरस और प्रस्तावित आर4सी विशेष कार्रवाई दर्शाते हैं। ई-कोर्ट, वीडियो सुनवाई और ई-समाधान न्याय तक समावेशी पहुंच बढ़ाते हैं।

---

## बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

**MCQ 1:** जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), जयपुर में आयोजित हुआ।
- यह साइबर सुरक्षा और न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था।
- साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**
**व्याख्या:** सम्मेलन आरआईसी, जयपुर में आयोजित हुआ और इसे तीन दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन के रूप में रखा गया। इसका विषय साइबर सुरक्षा को जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच से जोड़ता है। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिक जागरूकता को सबसे प्रभावी कवच के रूप में प्रमुखता दी गई।

---

**MCQ 2:** सम्मेलन में "डिजिटल अरेस्ट" के बारे में क्या कहा गया?
(a) यह साइबर अपराध मामलों में मान्यता प्राप्त न्यायिक प्रक्रिया है
(b) यह डिजिटल धोखाधड़ी में त्वरित गिरफ्तारी का वैध उपकरण है
(c) यह कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है और यह धोखाधड़ी का रूप है
(d) यह ई-कोर्ट पोर्टल के अंतर्गत चलने वाली पुलिस प्रक्रिया है

**उत्तर: (c)**
**व्याख्या:** जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि "डिजिटल अरेस्ट" नाम की कोई न्यायिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है और इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है। इसे पूर्णतः धोखाधड़ी बताया गया। यह संदेश नागरिकों को ऐसे ठग-तरीकों के प्रति सतर्क करने और ऐसे दावों के आगे झुकने से रोकने के उद्देश्य से दिया गया।

---

RASonly

**MCQ 3:** कार्यक्रम में बताए गए उपायों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- मुख्यमंत्री ने राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की।
- राज्य सरकार ने "ऑपरेशन एंटी वायरस" के तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई का उल्लेख किया।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत मंच "ई-समाधान" का शुभारंभ किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 केवल
(b) 1 और 2 केवल
(c) 2 और 3 केवल
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (d)**
**व्याख्या:** कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही "ऑपरेशन एंटी वायरस" के तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन मध्यस्थता और लोक अदालत से जुड़े मंच "ई-समाधान" की शुरुआत भी की, जिससे न्याय तक पहुंच अधिक सुलभ बनाने की दिशा में कदम मजबूत हुआ।

RASonly

RASonly